PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Times of India, Delhi
Wednesday 8th January 2014, Page: 28
Width: 4.48 cms, Height: 12.28 cms, a4, Ref: pmin.2014-01-08.31.204

Slowdown to hit fresh jobs: Crisil

New Delhi: The economic slowdown and falling labour intensity will force individuals to either work in farms or stay unemployed as 25% fewer jobs will be created in the manufacturing and services sector between 2012-13 and 2018-19, ratings and research firm Crisil said on Tuesday.

In a report, it said 38 million jobs will be created in FY 2013-19 compared with 52 million seen in FY 2005-12. "As a consequence, an additional 12 million people will be redirected to the farms in FY 2013-19. During FY 2005-12, there was a decline of 37 million in agriculture," it said. Crisil suggested investment in infrastructure should be accelerated, more money should be spent on health and education, as well as skill development, besides encouraging labour-intensive manufacturing through a focus on sectors such as textiles, leather and food processing. TNN

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Mail Today, Delhi
Wednesday 8th January 2014, Page: 25
Width: 4.95 cms, Height: 13.07 cms, a4, Ref: pmin.2014-01-08.32.72

REBEL TO LEAD PACK OF SPEED MONSTERS

GAUTAM Singhania, chairman and managing director, Raymond Group, and the founding chairman of Super Car Club, will lead the Park Super Car Show, 2014, in Mumbai on Sunday. Singhania told the media that the Hot Rod-Rebel, the 1932 built, by Ford, will be one of the major attractions of the sixth edition of the show.

Super Car Club has partnered with Omkar Realtors and Developers to organise the show. The show will display iconic cars like Lamborghini, Aston Martin, Ferrari, Porsche, Rolls-Royce Bentley, Audi and Mercedes. Since its launch in April 2009, every single year the number of supercars on display has increased and so has the number of people visiting the show which has grown in its stature as a world class automobile extravaganza.

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindustan, Delhi
Wednesday 8th January 2014, Page: 7
Width: 16.95 cms, Height: 13.92 cms, a4, Ref: pmin.2014-01-08.50.78

गृह मंत्रालय ने दी सैद्धांतिक मंजूरी, अब कैबिनेट के सामने आएगा प्रस्ताव

रेलवे में एफडीआई को हरी झंडी

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

गृह मंत्रालय ने भारतीय रेलवे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बतातें हैं कि मंत्रिमंडल जनवरी में इस पर अपनी मुहर लगा सकता है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से भारतीय रेलवे के आधुनिकीरण में गति आएगी। रेलवे के मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे हाई स्पीड ट्रेन गलियारा, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी), व्यवसायिक ट्रैक आदि को तेजी से पूरी किया जा सकेगा।

रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन बोर्ड (डीआईपीपी) ने वित्तीय संकट से गुजर रही रेलवे में 100 फीसदी एफडीआई का प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास भेजा था। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। उन्होंने बताया कि इस महीने प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि वहां भी इसे मंजूरी मिल जाएगी।

रेलवे में 100 फीसदी एफडीआई से धन के संकट से जूझ रही रेल परियोजनाओं में तेजी आएगी। हालांकि, ट्रेन परिचालन, टिकट बिक्री, रेल संरक्षा आदि क्षेत्र में एफडीआई पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा। लेकिन रेलवे के मेगा प्रोजेक्ट हाई स्पीड कॉरिडोर को पंख लग जाएंगे। इस कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेनें (300-350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार) चलाने की घोषणा कई साल पहले हुई थी। लेकिन धन के अभाव में यह योजना फाइल से बाहर नहीं आ सकी। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडार के निर्माण में तेजी आएगी। दोनों परियोजनाएं विश्व बैंक और जापान की सहायता से चल रहे हैं। शेष डीएफसी प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा सकेगा। इसके अलावा रेलवे के बुनियादी ढांचे का विकास औद्योगिक उद्देश्य के लिए किया जा सकेगा। प्रस्ताव के मुताबिक बंदरगाह, कोयला खदाने व औद्योगिक क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए व्यवसायिक ट्रैक बिछेंगे।

मुस्लिमों को भी एससी-एसटी की तरह छूट

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के तहत चल रही शिक्षण-प्रशिक्षण की योजनाओं में शुल्क छूट का लाभ लेने में मुस्लिम छात्र-छात्राओं को अब आसानी होगी। एक अंतरमंत्रालयी समूह ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की भांति मुस्लिम बच्चों को भी सीधे शुल्क से छूट देने की सिफारिश की है। जबकि अभी मुस्लिम छात्रों को छूट का लाभ लेने के लिए पहले शुल्क चुकाना पड़ता है बाद में सरकार उसे वापस करती है।

शिक्षण-प्रशिक्षण शुल्क

- अंतरमंत्रालयी समूह ने की सिफारिश, छात्रों को सीधे मिल सकेगा लाभ
- विभिन्न मंत्रालयों के बीच बनाई जा रही है आमसहमति, केंद्र इसपर जल्द लेगा फैसला

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस पर आम सहमति बनाई जा रही है। जल्द फैसला होगा। एक अधिकारी के अनुसार मानव संसाधन के अलावा, अल्पसंख्यक मंत्रालय, कृषि, वस्त्र, सामाजिक न्याय समेत कई मंत्रालयों में शिक्षक से जुड़ी योजनाओं में मुस्लिम छात्रों को शुल्क से छूट प्रदान है। लेकिन उन्हें पहले शुल्क चुकाना होता है फिर सरकार उन्हें वापस लौटाती है। इस प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। जबकि एससी, एसटी के मामले में यह छूट सीधे प्राप्त है। मसलन यदि किसी संस्थान में एससी, एसटी छात्रों को शुल्क छूट है तो संस्थान सीधे इसका क्लेम संबंधित विभाग से करता है।

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Bhaskar, Faridabad
Wednesday 8th January 2014, Page: 4
Width: 27.42 cms, Height: 11.03 cms, a3r, Ref: pmin.2014-01-08.54.49

राहत की बात ▶ अप्रैल से नवंबर के दौरान गैर-पारंपरिक देशों में 15-20 फीसदी बढ़ा निर्यात

सुस्ती से अपैरल निर्यातकों को नए बाजारों ने उबारा

मिला सहारा

आर्थिक सुस्ती के चलते अपने पारंपरिक बाजार अमेरिका व यूरोप से निराश हुए अपैरल निर्यातकों को गैर पारंपरिक बाजारों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, कोलंबिया, पनामा, उरुग्वे, चिली, जापान, कोरिया, रूस, यूनाइटेड अरब अमीरात और सउदी अरब से सहारा मिला है।

17
अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य पाना कठिन चालू वित्त वर्ष में

15
फीसदी अमेरिका व यूरोप में 24 फीसदी घटा निर्यात अप्रैल-नवंबर के दौरान

बिजनेस भास्कर ▶ **चंडीगढ़/लुधियाना...**

आर्थिक सुस्ती के चलते अपने पारंपरिक बाजार अमेरिका व यूरोप से निराश हुए अपैरल निर्यातकों को गैर पारंपरिक बाजारों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, कोलंबिया, पनामा, उरुग्वे, चिली, जापान, कोरिया, रूस, यूनाइटेड अरब अमीरात और सउदी अरब से सहारा मिला है। चालू वित्त वर्ष में नवंबर में भले ही अपैरल का निर्यात 15 फीसदी बढ़ा है, पर अप्रैल से नवंबर दौरान जहां पारंपरिक बाजारों में भारतीय अपैरल का निर्यात 10 से 24 फीसदी घटा है, वहीं गैर-पारंपरिक बाजारों में निर्यात 15-20 फीसदी तक बढ़ा है।

अपैरल निर्यातकों के अनुसार गैर-पारंपरिक बाजारों में वृद्धि होने की वजह से ही निर्यात की गिरावट पहली छमाही में कम रही है, नहीं तो यह गिरावट और भी अधिक हो सकती थी। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के उत्तरी क्षेत्र के वाइस चेयरमैन एचकेएल मग्गो के मुताबिक पारंपरिक बाजार अमेरिका व यूरोप को अप्रैल-नवंबर 2012 में इन देशों को 6.4 अरब डॉलर निर्यात चालू वित्त वर्ष की समान अवधि में घटकर 5.7 अरब डॉलर रह गया। इस दौरान अमेरिका में भारतीय अपैरल का निर्यात 10 फीसदी और यूरोप में 24 फीसदी घटा है। गैर-पारंपरिक बाजारों में निर्यात बढ़ने से यह गिरावट औसतन 10 से 12 फीसदी रही है। कोरिया में निर्यात वृद्धि पिछले साल के मुकाबले 24 फीसदी, पनामा में 10 फीसदी, यूनाइटेड अरब अमीरात में 10 फीसदी, सऊदी अरेबिया में 7 फीसदी और कोलंबिया में एक फीसदी रही है। मग्गो के मुताबिक पारंपरिक बाजारों अमेरिका और यूरोप में मांग कमजोर और कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के बीच चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारत से कुल अपैरल निर्यात लक्ष्य 17 अरब डॉलर को हासिल करना मुश्किल होगा। इसलिए हम गैर-पारंपरिक बाजारों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए सरकार और एसोसिएशन के स्तर पर विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। नवंबर में पनामा-कोलंबिया में एक बायर-सेलर मीट का आयोजन किया गया था। फैडरेशन ऑफ निटवियर एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत लाकड़ा के मुताबिक पहले अमेरिका और यूरोप से ही इतने ऑर्डर मिल जाते थे कि दूसरे बाजारों पर ध्यान ही नहीं दे पाते थे। लेकिन इस साल यहां से 20 फीसदी ऑर्डर कम हैं। ऐसे में यदि हमें कोई नया बाजार मिलता है तो हम वहां से ऑर्डर हासिल करने की हर संभव कोशिश करते हैं। यह हमारे लिए सुस्ती से लड़ने का बहुत अच्छा जरिया है। नेचवा गारमेंट्स के सीईओ विशाल जैन के मुताबिक यूएस के साथ वियतनाम, मैक्सिको और इंडोनेशिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। रूस, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया जैसे देश हमारे लिए तेजी से उभरते बाजार हैं।